

LOK SABHA DEBATES

1

LOK SABHA

*Tuesday, February 18, 1969 Magha 29, 1890
(Saka)*

*The Lok Sabha met at Eleven of the
Clock.*

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCE

MR. SPEAKER : I have to inform the House of the sad demise of Shri Beli Ram Das who passed away at Gauhati on the 14th January, 1969 at the age of sixty.

Shri Beli Ram Das was a Member of the First Lok Sabha during the years 1952-57. We deeply mourn the loss of this friend and I am sure the House will join me in conveying our condolences to the bereaved family.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : I have had the proud privilege of knowing Mr. Beli Ram Das very intimately for over a decade. He was a member of the Scheduled Castes and gave the best expression to our national aspirations. He was a valiant fighter for the freedom of India. He gave our nationalist aspirations the best expression. On behalf of our Party, we deeply mourn the loss of Beli Ram Das who as a Member of this House made distinctive contributions to the deliberations of this House.

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : Shri Beli Ram Das was one of the diminishing number of our old freedom fighters who joined the freedom struggle in 1921. He worked in many fields but was

2

specially interested in the welfare of Harijans as well as the Scheduled Tribes. We deeply mourn his loss and request you to convey our condolences to the bereaved family.

MR. SPEAKER : The House may stand in silence for a short while to express its sorrow.

The Members then stood in silence for a short while.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Central Advisory Council for Industries

*1. SHRI P. M. SAYEED :

SHRI MANIBHAI J. PATEL :

SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI :

SHRI CHENGALRAYA NAIDU :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a meeting of the Central Advisory Council for Industries was held in the beginning of January, 1969; and

(b) if so, the topics discussed and the main decisions arrived at as a result thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATHA REDDY) : (a) and (b). Yes, Sir. The meeting of the Central Advisory Council of Industries reviewed the general economic situation and industrial development in the country and also considered matters having a bearing on industrial licensing policy. Suggestions/observations made by members related to

foreign collaboration, avoidance of repetitive import of know-how, supply of raw materials, import substitution, export promotion, expansion of marketing facilities, the need for arousing cost consciousness and improvement of labour relations.

SHRI P. M. SAYEED : The hon. Minister informed us of the decisions taken by the Advisory Council for Industries. Was any decision taken with regard to the regional imbalances in the country? What is the total outlay in industries in the country which are not giving any output?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : The subjects, we discussed in the last meeting have been indicated. The matter relating to regional imbalances was not discussed in the last meeting.

If the hon. Member gives me notice, I shall give him information on outlays which he wants to know.

SHRI P. M. SAYEED : What is the outlay on industries earmarked for the Laccadive Islands?

SHRI F. A. AHMED : I have not got the figures.

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : इस समय हमारे देश में कुछ बड़े-बड़े कोलेबोरेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऐग्रीमेंट में यह शर्त लगा रखी है कि उन का माल निर्यात नहीं किया जायेगा। क्या यह ठीक है कि हमारे उद्योग मंत्री ने उम बैठक में यह वादा किया था कि ऐसे केसेज रिन्यूअल के लिये प्रायेंगे तब या तो उनकी यह शर्त हटा दी जायेगी जिस से कुछ चीजों के निर्यात पर रोक लगी हुई है या जो उन के परमिट हैं, ऐग्रीमेंट है उनको रिन्यू नहीं किया जायेगा?

श्री कलशचरित्त जली ब्रह्मचर : जहां तक उन ऐग्रीमेंट्स का तात्सुक है जो पहले हो चुके हैं और जिन में यह क्लॉज है कि बाहर मान

भेजने की मुमानियत है, उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसे केसेज हमारे पास रिन्यूअल के लिये आते हैं तब हम ऐसे रेस्ट्रिक्शन्स को हटाने की कोशिश करते हैं और वह हटाये जा रहे हैं।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : May I know whether it is a fact that most of the members of the Central Advisory Council have complained against the procedural delays on the part of the Government which has seriously hampered the economic progress of the country? It has also been pointed out that the delay on the proposed Tata fertiliser project has caused a loss of Rs. 25 lakhs every day to the country. Is it also a fact that the Mysore Chief Minister also has complained about the delay of the Government in sanctioning these industries?

SHRI F. A. AHMED : So far as the question of the fertiliser project is concerned, the specific matter was raised by one of the members of the Council. So far as the matter relating to the Mysore Government is concerned, it is not only a question of licence being issued by the Committee, but whether there is provision of the necessary finances for implementing the licence. I do not know which matter the hon. Member has in view, but we have not raised any difficulty of the finances available for implementing a project.

श्री कंबरलाल गुप्त : यह सरकार डिले, रेडटेपिज्म, करप्शन आदि की मौलिक बीमारी से मुक्तला है। इस सिलसिले में टाटा ने, जो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, शिकायत की थी कि प्राइवेट सेक्टर के जो प्रोजेक्ट सैंकशन होते हैं, उन की लाइसेंसिंग और उन को रामेंटी-रियल वगैरह मिलने में बहुत डिले होती है, जिस से प्रोडक्शन का बहुत नुकसान होता है। पहले 7 और 8 परसेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ता था, 1967-68 में वह 1 परसेंट रह गया, और इस साल करीब 5 परसेंट बढ़ने की उम्मीद है। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह जो दिक्कतें हैं, डिले होने की, रेडटेपिज्म, करप्शन वगैरह की, उन को दूर करने के लिये क्या सरकार ने कोई खास कदम उठाये हैं?

दूसरी बात में यह जानना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रीज का डिलाइमेंसिंग करने केलिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री फखरुद्दीन खली अहमद : जहाँ तक खास प्रोजेक्ट का ताल्लुक है,...

श्री कंबरलाल गुप्त : मैंने खास प्रोजेक्ट की बात नहीं कही है।

श्री फखरुद्दीन खली अहमद : जहाँ तक खास प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, जिसका जिक्र, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, टाटा साहब ने किया है, उसमें हमारी डिने का सवाल नहीं है। उसके ऐक्स्पेंशन के लिये यह देखना है कि उसमें क्या फायदा या नुकसान होना है, और इन दोनों चीजों को देखकर उस पर फैसला करना है।

जहाँ तक लाइसेंसिंग का ताल्लुक है, हम ने अभी नई पालिसी के जरिये से इस बात को शुरू किया है कि लाइसेंसिंग वगैरह जल्दी से जल्दी डिस्पोजिबल हो जाने चाहिये। हम ने एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड मुकर्रर किया है। इस मिलिमिने में यह तय किया गया है कि जो लाइसेंसिंग। करोड़ रुपये से कम के होंगे उन्हें मिनिस्ट्री डिस्पोजिबल कर देगी। लेकिन अगर दरखास्त घाने के छः महीने के अन्दर वह डिस्पोजिबल नहीं करती है तो उसको इन्वेस्टमेंट बोर्ड डिस्पोजिबल करेगा। दूसरे इन्वेस्टमेंट बोर्ड के पास जो कैसेज प्रायेंगे, अगर वह छः महीने के अन्दर डिस्पोजिबल नहीं हो तो उनको कॅबिनेट देखकर डिस्पोजिबल करेगी। उम्मीद है कि इससे लाइसेंसिंग वगैरह में जो डिफे होनी थी वह नहीं होगी। हम हर महीने में देख रहे हैं कि कौन-कौन से कैसेज कितने पुराने पड़े हुए हैं और वह कितनी जल्दी डिस्पोजिबल हो रहे हैं। हमारी कोशिश यह है कि हम जल्दी से जल्दी उन को डिस्पोजिबल कर दें। अगर घानेबल मेम्बर के अन्दर में कोई ऐसा केस प्राये जो पुराना पड़ा हुआ है और उसका फैसला

नहीं हुआ है तो वह बतलायें हम उसकी तहकीकात करेंगे।

श्री कंबरलाल गुप्त : डीलाइमेंसिंग के बारे में भी बताया है।

श्री फखरुद्दीन खली अहमद : जैसा कि घानेबल मेम्बरज को मालूम है प्लानिंग कमिशन ने वह प्रोपोजल दी है कि जहाँ हम को बाहर के फोरन एक्सचेंज की जरूरत न हो और हमारी कोशिश से ही इंडस्ट्री यहाँ बन सकती हो तो ऐसी इंडस्ट्रीज को डीलाइमेंस कर दिया जाना चाहिये। दूसरे उन्होंने यह भी कहा है कि जहाँ थोड़े से फारेन एक्सचेंज की जरूरत हो उसकी भी डीलाइमेंस कर दिया जाना चाहिये। जब यह चीज वहाँ फाइनल हो जाएगी तो गवर्नमेंट इस पर डिजिशन लेगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा। स्माल इंडस्ट्रीज को बचा कर हम को डीलाइमेंसिंग वगैरह के बारे में फैसला करना पड़ेगा।

MR. SPEAKER : Shri Sheo Narain.

SHRI SHEO NARAIN *Rose*—(Interruptions). : We are returning from the mid-term polls, and see the behaviour of our friends ! Coming events cast their shadows before. I want to know from the Minister what he is going to do to help small industries in small places by which we can give food and clothing to the poor people.

SHRI F. A. AHMED : The question relates to scheduled industries. The policy of the Government is to encourage small-scale industries all over the country as much as possible.

SHRI PILOO MODY : From the speech of the hon. Minister, one would imagine that from now on industries will be licensed at the rate of one every five minutes. I do not know whether he is aware of the fact that there is something like 1500 to 1800 applications lying on his desk accumulated over the last so many years. When he has assured us

that he is going to start licensing them very quickly, I want to know whether he is going to start at the top or at the bottom or in the middle of the pile.

SHRI F. A. AHMED : Despite the humour introduced by my hon. friend, the question of so many years does not arise, because I have been in charge of the ministry for only two years and I can assure him that not even one application for licence is lying on my table.

श्री फ्रेम अहमद अर्मा : क्या यह सच है कि सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल फार इंडस्ट्रीज में देश के चन्द पूजीपतियों, चन्द खानदानों की ही प्रकसरियत है और पब्लिक सेक्टर, स्माल और मीडियम इंडस्ट्रीज की वहाँ नुमाइंदगी न के ही बराबर है जिसके कारण बड़े बड़े इंडस्ट्रीयलिस्ट सरकार जो पालिसी बनाना चाहती है उस पर हावी हो जाते हैं ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि पब्लिक सेक्टर प्रॉडरटेकिंग और स्माल और मीडियम साइज इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी नुमाइंदगी इस काउन्सिल में ज्यादा हो ताकि सरकार जो पालिसी बनाती है उस पर वे भी अपने विचार रख सकें ?

श्री फल्लहदीन अली अहमद : यह बात गलत है कि सिर्फ एक ही तबके के लोगों को हम वहाँ रिप्रिजेंटेशन देते हैं। चूंकि यह एडवाइजरी काउंसिल फार शैड्युल्ड इंडस्ट्रीज है इसलिए जिन लोगों का इससे ताल्लुक है उनको हम मेम्बर बनाते हैं। उसी के साथ साथ स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज, सेक्टर और दूसरे लोगों को भी हम इस में रिप्रिजेंटेशन देते हैं और उनका रिप्रिजेंटेशन काफी है। उनको जो बात कहनी होती है उसको कहने का उनको इस काउन्सिल में मौका मिलता है और उस पर हम लोग सोचते हैं और विचार करते हैं।

SHRI UMANATH : In the January meeting of the Council, I understand some members raised the question of continued issuance of licences to new Birla firms. I also understand that certain members expressed the opinion

that in view of the fact that the Government is investigating into the irregularities various Birla firms and certain remarks made in the Hazare Report about misuse of licences by Birlas, Government should stop issuing any new licence to Birlas, until a decision is taken on the question of investigation. If this is true, I would like to know from the Government what steps Government contemplate to stop the issue of new licences to Birlas till the investigations are over ? If no steps are going to be taken, may I know the reasons ?

SHRI F. A. AHMED : As far as I remember, no such specific case was raised in this Council.

SHRI UMANATH : Let the Minister make himself sure that no such thing was raised in this Council, otherwise he will face another resolution here.

SHRI NARENDRA KUMAR SALVE : The story of delays in the matter of sanctioning licences and ancillary matters by this Ministry is a tale of unbased misfortune for the country that impedes and stultifies the pace of industrial growth. That is why in the meeting of this Council, to which this question refers, Shri Tata came out with a very scathing criticism of this Ministry. I will read out what he said.

MR. SPEAKER : The hon. Member may kindly resume his seat. This is the Question Hour. The hon. Member cannot make a speech now. He cannot read out the speech of Shri Tata. Everybody has read it.

SHRI NARENDRA KUMAR SALVE : There was resentment in the Committee over the delays caused by the Ministry in processing licences and clearing applications for licences. Same is the story heard from Shri Virendra Patil of Mysore. We have ourselves seen it in the case of manufacture of precision instruments and precision tools at Nagpur. It has not been cleared. If the Minister is sure that there is no delay being caused and the Ministry is taking sufficient steps, my question is whether the hon. Minister is willing to assure the House that he would consider appointing a committee with some Members of Parliament on it to go into this matter of delay in clearing the industrial projects and suggest remedies therefor ?

SHRI F. A. AHMED : Perhaps the hon. Member is not aware that under one of the provisions of the Industrial Regulation Act a committee already exists of non-official members. I do not now remember the names of members associated with it from this House. But Members of this House have been associated with it. They go into the question of licences granted, rejected and which are kept pending, and also deal with the specific cases where there was delay.

श्री रवि राय : मेंट्रल एडवाइजरी कौंसिल फार इंडस्ट्रीज की बैठक में क्या विदेशों से जो टेक्नीकल नो हाऊ आयात होता है उसके बारे में भी चर्चा हुई थी ? सालाना कितना रुपया हमारा खर्चा होता है विदेशों से टेक्नीकल नो हाऊ का आयात करने में और चौथी योजना में कितना होने का अंदाजा है और इसको घटाने के लिए सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ?

SHRI F. A. AHMED : Sir, I can give the exact figures, but I have not got them with me at present. The question with regard to technical know-how was discussed in a general form but not in a specific manner.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : May I know from the hon. Minister, since he came into power only during the last two years, how many licences during these two years have been issued to those houses who had been mentioned as monopoly-houses in the Monopoly Commission's Report, how many licences have been issued State-wise, and whether any particular State, A or B, has got more licences ? May I also know whether it is a fact that it has not removed the regional imbalance so far as industry is concerned ? Thirdly, I would request him to place before the House at least the interim recommendations of the Industrial Licensing Review Committee which is taking so long to submit its report to this House ?

SHRI F. A. AHMED : I want notice for this question, and the report will be placed before the House.

MR. SPEAKER : Shri Hem Barua.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI :

What about my first two questions to which I have not received any reply ?

SHRI F. A. AHMED : The hon. Member wants certain figures. I said that I want notice. So far as the report is concerned, the latest report of the committee will be placed on the Table of the House.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Since the Industrial Advisory Council has discussed this matter, it comes within the purview of this question.

MR. SPEAKER : He is not ready with the figures ; he wants time.

SHRI HEM BARUA : In view of the fact that regional imbalances in industrial development is one of the main reasons for the deep-seated resentment in certain parts of the country, particularly in Orissa, West Bengal and Assam—in Assam the number of people unemployed is 4 lakhs; please do not forget that—in view of that, may I know what steps are being taken by the government, as assured by the hon. Minister on the floor of the House during the last session, to remove regional imbalances in order to root out the causes for unemployment in the country ?

SHRI F. A. AHMED : The question of regional imbalance is a very complicated one. It is not only related to one State *vis-a-vis* another but also within one State itself. This matter has been engaging our attention. The Planning Commission had appointed two groups to examine the question and give their recommendations. In fact, we are ready with our recommendations to place them before the government; but are waiting for the report of the working group so that we may co-ordinate these two reports and then place the recommendation before the government.

SHRI HEM BARUA : The Planning Commission has done nothing up till now.

SHRI F. A. AHMED : They have set up a working group. When that report is available we will consider it along with our report and then take a decision as to how to tackle this problem.

SHRI KARTIK ORAON : I would like to know from the hon. Minister the composition of

the Central Advisory Council for Industries in terms of the number of industrialists, industrialists with technical background, technical personnel and Members of Parliament, if any, and the criteria laid down for the selection of members for the Central Advisory Council for Industries.

SHRI F. A. AHMED : Sir, if you so direct, I can place a list of members of the Council before the House which will give an indication of the composition of members of the Council. Representation has been given in the Council for industrialists, manufacturers, consumers, labour and so on.

SHRI INDRAJIT GUPTA : It was reported after this meeting of the Central Advisory Council that the big industrialists who are members of this Council had pressed for further relaxation and almost total withdrawal of whatever restrictions still remain on foreign collaboration by the private sector. I want to know whether as a result of this demand the government has decided, and if so, in what specific respects, to remove the existing restrictions which remain only on paper of the Industrial Policy Resolution ?

SHRI F. A. AHMED : There is no question of removing any restriction. Whenever a proposal comes before us we take into consideration the interests of the country and our whole idea is that we should not only receive foreign technical know-how but we should also start developing it. It is from this point of view that all the proposals are being considered by the Ministry.

SHRI INDRAJIT GUPTA : It was not my question. Am I to take it that they have refused to remove the restrictions ? What is the answer, because a demand has been made ?

SHRI F. A. AHMED : We have not removed the restriction.

SHRIMATI SUDHA REDDY : Will the hon. Minister bear in mind the suggestion of the Chief Minister of Mysore that industries could increasingly be located in such States where two very rare raw materials are available, namely, climate of peace and stability of power ?

SHRI F. A. AHMED : They are valid for all industries.

Commission on Railway Safety

*2. **SHRI K. M. ABRAHAM :**

SHRI NAMBIAR :

SHRI V. NARASIMHA RAO :

SHRI HEM RAJ :

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR :

SHRI A. SREEDHARAN :

SHRI S. K. TAPURIAH :

SHRI SHRICAND GOYAL :

SHRI KARNI SINGH :

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY :

SHRI SAMAR GUHA :

SHRI RABI RAY :

SHRI RAM SWARUP VIDYRTHI :

SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN :

SHRI NARAIN SWARUP SHARMA :

SHRI BANSH NARAIN SINGH :

SHRI ONKAR SINGH :

SHRI K. M. MADHUKAR :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Commission on Railway Safety has criticised the Railway Board in its report for 1966-67;

(b) if so, the main points of criticism ;

(c) whether Government have examined the report; and

(d) if so, the decision taken on each recommendation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI PARIMAL GHOSH) : (a) and (b). The report has already been placed on the Table of the House.

(c) Yes, sir.

(d) It is a narrative report and does not contain any recommendation. It, however, makes a mention of the various recommendations made by the Commission, arising out of its inspections, sanctions